

सामान्य अध्ययन - (प्रश्न - पत्र IV)

GENERAL STUDIES (Paper IV) (2025)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बारह प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखते।

प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting question.

There are **TWELVE** Questions divided in **TWO SECTIONS** and Printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided.

NO marks will be given for answer written in a medium other than the authorized one.

Keep the word limit indicated in the question in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

- Q 1. (a)** “दयालुता के छोटे-छोटे कार्य सूक्ष्म होते हैं और आमतौर पर ध्यान नहीं दिए जाते, लेकिन वे एक नैतिक मानव व्यक्तित्व के सबसे स्पष्ट संकेत होते हैं।” हमारे दैनिक जीवन में दयालुता के ऐसे छोटे-छोटे कार्यों के नैतिक परिणाम क्या हैं?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“Small acts of kindness are subtle and usually go unnoticed but they are the most clear signs of an ethical human personality.” What are the ethical consequences of such small acts of kindness in our daily lives?

10

(Answer in 150 words)

- (b)** “परिवार में बचपन में अनुभव किए गए प्रेम, देखरेख और सहयोग पर आधारित प्रारंभिक जुड़ाव जीवन के बाद के चरणों में सेवा के मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“The initial bonds in the family based on love, care and cooperation experienced during childhood prove crucial in the development of the value of service in the later stages of life.” Examine the statement with relevant examples.

10

(Answer in 150 words)

- Q2. (a)** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो व्यापक मॉडल हो सकते हैं, एक साझेदारी और साझा विकास पर आधारित और दूसरा अलगाव और राष्ट्रीय स्वार्थों पर आधारित। इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को चुनने के लिए कौन से नैतिक विचार प्रेरित कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए।

There can be two broad models of international relations, one that is based upon partnership and shared growth and the another based upon isolation and national self-interests. What ethical considerations could motivate to choose either of the approaches? Explain.

10

(Answer in 150 words)

- (b)** ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता जाल हमारे दैनिक जीवन में गहराई से पैठ बना चुका है और बाजार संबंधों और उपभोक्ता अभिवृत्ति को परिवर्तित कर रहा है। इस संदर्भ में ई-कॉमर्स द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों पर नैतिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“The rapidly growing web of e-commerce has penetrated deep into our daily lives transforming the market relations and consumer attitude.” Discuss from an ethical point of view the key changes e-commerce has brought in this context.

10

(Answer in 150 words)

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

- Q 3.** महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?

Given below are three quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context?

- (a) “यदि आप इसलिए रोते हैं कि आपके जीवन से सूर्य चला गया है, तो आपके आँसू आपको तारे देखने से रोक देंगे।” – रवींद्रनाथ टैगोर

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars.” - Rabindranath Tagore

10

(Answer in 150 words)

- (b) “न्यायालयों से भी ऊँचा एक न्यायालय है और वह है अंतरात्मा का न्यायालय। यह अन्य सभी न्यायालयों से श्रेष्ठ है।” – महात्मा गांधी

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.” - Mahatma Gandhi

10

(Answer in 150 words)

- (c) “अपने उद्देश्य के साथ पूर्णतया तादात्म्य सफल नेतृत्व की पहली और महान शर्त है।” – वुडरो विल्सन

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“Absolute identity with one's cause is the first and great condition of successful leadership.” - Woodrow Wilson

10

(Answer in 150 words)

- Q4. (a)** “एक सिविल सेवक प्रशासन की कुंजियों का स्वामी नहीं, बल्कि संभालने वाला होता है। यह धारणा सिविल सेवाओं के लिए आधारभूत मूल्यों को सुदृढ़ कर सकती है और आवश्यक अभिवृत्ति विकसित कर सकती है।” उपरोक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“A civil servant is not the owner but the handler of the keys of administration. This notion can strengthen foundational values and develop the required attitude for civil services.” Examine the above statement with suitable examples.

10

(Answer in 150 words)

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

- (b) “अपने और दूसरों के लिए अलग-अलग मानदंड एक सकारात्मक कार्य वातावरण का निर्माण नहीं कर सकते। मानदंडों में समानता कार्यस्थल पर समानता की दिशा में पहला कदम है।” उपरोक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“Different sets of norms for oneself and others cannot build a positive work environment. Equality in norms is the first step towards equality at the workplace.” Examine the above statement with suitable illustrations.

10

(Answer in 150 words)

- (a) भ्रष्टाचार तब उत्पन्न होता है जब छोटे-छोटे सुख जीवन के बड़े उद्देश्यों पर हावी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मूल समाधान केवल कानूनी बल पर निर्भर रहने के बजाय नैतिक बल से प्राप्त किया जा सकता है। सिविल सेवा के उच्चतर उद्देश्यों के प्रति सिविल सेवकों को निरंतर उन्मुख करने के उपाय सुझाइए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Corruption arises when the larger purposes of life are taken over by small pleasures of being. The root solution of corruption would be achieved through moral force as compared to sole reliance on legal force. Suggest measures to continuously orient the civil servants towards the higher objectives of the civil service.

10

(Answer in 150 words)

- (b) “लोक सेवा गारंटी अधिनियम सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की वास्तविक पूर्ति सुनिश्चित करते हैं और साथ ही नागरिकों के सेवाओं के अधिकार को रेखांकित करते हैं।” ये कानून नागरिकों को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं? नैतिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“Public Services Guarantee Acts ensure the actual delivery of commitments made by the government as well as underscore citizens’ entitlement to services.” How do these legislations empower the citizens? Discuss from an ethical point of view.

10

(Answer in 150 words)

- Q6. (a) “सरकार में क्षेत्र विशेषज्ञों को लाने की प्रथा सिविल सेवा में नए विचारों, प्रतिभाओं और विविध अनुभवों को लाने के तर्क पर आधारित है। लेकिन भारत में हाल के दिनों में ऐसे प्रयासों ने काफी विवाद उत्पन्न किया है।” शासन-व्यवस्था के दार्शनिक आधार बनाने वाले सिद्धांतों के प्रकाश में इस कथन की चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“The practice of bringing domain experts into the government is based on the rationale to bring in fresh ideas, talents, and diverse experiences into civil services. But such attempts in the recent past in India have generated much controversy.” Discuss the statement in light of principles that form the philosophical basis of governance. 10

(Answer in 150 words)

- (b) वृद्धों का सम्मान और देखभाल भारतीय संस्कृति और लोकाचार का अभिन्न अंग है। हालाँकि, विशेष रूप से समाज के संपन्न वर्गों में माता-पिता को वृद्धाश्रमों में रखने का चलन बढ़ रहा है। बदलती मूल्य प्रणालियों और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रकाश में इस प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Respect and care for elderly is integral to Indian culture and ethos. Though there is an increasing trend of admitting parents to old-age homes particularly among well-off sections of the society. Discuss this trend in light of changing value systems and social realities. 10

(Answer in 150 words)

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

SECTION – B

Q 7. दिव्या एक युवा आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में एक ग्रामीण जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने सिविल सेवा में अपने छोटे से करियर में ही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ख्याति अर्जित की है। राज्य सरकार ने उस जिले के चार गाँवों को एक प्रमुख सौर फार्म परियोजना के स्थान के रूप में चिह्नित किया है, जिसे एक प्रसिद्ध निजी कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 2,500 एकड़ उत्पादक कृषि भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक है, जिससे सैकड़ों किसान परिवार विस्थापित होंगे, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को भी प्रभावित करेगा क्योंकि यह जिला भूमिहीन मजदूरों, छोटे व्यापारियों और कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं की एक जीवंत स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

दूसरी ओर, सौर पार्क सैकड़ों मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे ऊर्जा की कमी वाले राज्य को अत्यंत आवश्यक बिजली मिल सकेंगी। इसमें जिले की अनियमित बिजली आपूर्ति को स्थिर करने की भी क्षमता है, क्योंकि वर्तमान में इसे प्रायः बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना में सौर पैनल तकनीशियन, रखरखाव कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, रसद और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कार्यों आदि जैसे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें एक कौशल केंद्र की स्थापना, स्थानीय स्कूलों का उन्नयन, सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित करना आदि शामिल हैं।

हालाँकि, इस परियोजना के विरोध में किसानों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन के छिन जाने, अनुचित अधिग्रहण प्रक्रिया, अपर्याप्त मुआवजे और भविष्य में अनिश्चित आजीविका का डर है। हाल ही में ग्रामीणों, कंपनी के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में उनकी चिंता और बढ़ गई, जहाँ उन्हें अधिकारियों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों को सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। बैठक की घटनाएं ऑनलाइन वायरल हो गईं और मीडिया में भी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रिया हुई और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। किसान संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक, स्वच्छ ऊर्जा के समर्थक तो हैं, लेकिन बंजर या गैर-कृषि विकल्पों की बजाय उपजाऊ भूमि को चुनने की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच, दिव्या पर पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का दबाव है क्योंकि मुख्यमंत्री नियमित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही इस परियोजना की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और आगे निवेश आकर्षित करने की क्षमता को लेकर घोषणाएँ कर दी हैं।

- उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
- उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए दिव्या के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- विभिन्न हितधारकों के हितों की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिव्या को कौन से विशेष उपाय करने चाहिए?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Divya is a young IAS officer recently posted as a District Magistrate in a rural district. She had earned a reputation of getting projects completed on time in a short span of career in civil services. The state government has identified four villages in that district as the location for a flagship solar farm project to be developed by a well-known private company. The project requires acquiring 2,500 acres of productive agricultural land which will displace hundreds of farming families, most of them being small and marginal growers. It will also indirectly affect others as the district supports a vibrant local economy of landless labourers, small traders and agricultural input suppliers.

On the other hand, the solar park will generate hundreds of MW of clean energy providing much needed electricity to the energy deficient state. It also has the potential to stabilise the district's erratic electricity supply as it currently faces frequent outages. The project has the potential to create thousands of direct and indirect jobs such as solar panel technicians, maintenance staff, security personnel, logistics and supply chain roles etc. Additionally, the company has committed to corporate social responsibility (CSR) initiatives, including establishing a skills centre, upgradation of local schools, installing solar-powered irrigation systems etc.

However, the project has sparked widespread protests from farmers, who fear loss of their ancestral land, unfair acquisition process, inadequate compensation and uncertain future livelihoods. Their concern got credence in a recent meeting between villagers, company representatives and government officials where they had to face highhanded behaviour from the authorities. Those leading the protests were called out and threatened with severe consequences in presence of government officials. Incidents of the meeting went viral online and also widely reported in the media which received backlash from various quarters and intensified the protests. Farmer organisations, environmental activists and local citizens, while supportive of clean energy, criticize the choice of fertile land over degraded or non-agricultural alternatives. Meanwhile, Divya is facing pressure to expedite the entire process as the Chief Minister is personally monitoring it on a regular basis. He has already made announcements regarding the project's potential to meet national renewable energy deadlines and attract further investments.

- Discuss the ethical issues involved in the above case.
- What are the options available to Divya to tackle the above situation?
- What particular measures Divya should take to ensure that interests of different stakeholders are adequately met?

20

(Answer in 250 words)

- Q 8.** श्री अजीत एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं जो सामाजिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्वविद्यालय को वैश्विक संस्थानों से महत्वपूर्ण धनराशि प्राप्त होती है, जिसमें एक प्रमुख यूएस-आधारित फाउंडेशन भी शामिल है, जो इसके सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। हाल ही में विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न के एक गंभीर आरोप से हिल गया है। एक 22 वर्षीय महिला स्नातकोत्तर छात्रा ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उसने डॉ. विनायक, एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कई बार प्रकाशित होने चुके प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. विनायक, सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता से राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में विश्वविद्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों में 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध कराया है।

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

छात्रा की शिकायत में छह महीनों में हुई कई घटनाओं का विवरण है जिसमें निजी मेंटरिंग सत्रों के दौरान अनुचित टिप्पणियां, देर रात अनचाहे संदेश और एक घटना शामिल है जिसमें प्रोफेसर ने अपने कार्यालय में बंद दरवाजे की बैठक के दौरान कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ था। वह दावा करती है कि इन कार्यों ने एक नकारात्मक वातावरण बनाया, जिससे उसे कक्षाओं में न जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ा। उसने संदेशों के स्क्रीनशॉट और गवाह के रूप में एक साथी छात्र, को प्रस्तुत किया है, जिसने कुछ टिप्पणियां सुनी थीं। हालांकि, इस शिकायत ने विरोधाभास को जन्म दिया है। डॉ. विनायक के दो सहकर्मी, जो वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, का दावा है कि छात्रा का मुद्दों को “बढ़ा-चढ़ाकर” पेश करने का इतिहास रहा है और उनका संकेत है कि उसके आरोप कोर्स में खराब ग्रेड से प्रेरित हो सकते हैं। डॉ. विनायक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बातचीत पेशेवर थी और संदेशों को संदर्भ से बाहर समझा गया। उनके प्रभावशाली समर्थक हैं, जिनमें एक सांसद भी शामिल हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके योगदान की प्रशंसा की है। सांसद ने श्री अजीत से निजी तौर पर भी संपर्क किया था और संकेत दिया था कि इस मामले को आगे बढ़ाने से विश्वविद्यालय की फंडिंग और प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है।

एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली आईसीसी पर पॉश अधिनियम द्वारा निर्धारित 90-दिवसीय समय-सीमा के भीतर जाँच में तेजी लाने का दबाव है। अमेरिका स्थित फाउंडेशन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि निरंतर फंडिंग विश्वविद्यालय की नैतिक शासन की प्रतिष्ठा बनाए रखने पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक ईमेल लीक से पता चला है कि एक वरिष्ठ शिक्षक ने छात्रा को मामले का “समाधान” करने और अपनी शिकायत वापस लेने के बदले में छात्रवृत्ति देने की पेशकश की थी। इससे तनाव और बढ़ गया है। रजिस्ट्रार के रूप में श्री अजीत यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि आईसीसी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पॉश अधिनियम के अनुरूप हो, साथ ही विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, फंडिंग और आंतरिक शैक्षणिक संरचना का प्रबंधन भी सुनिश्चित हो। गवर्निंग काउंसिल के दबाव में कुलपति ने रजिस्ट्रार से ऐसी कार्यवाही की सिफारिश करने को कहा है जो छात्रा के लिए न्याय और विश्वविद्यालय के हितों के बीच संतुलन बनाए रखे। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराधों में वृद्धि के बीच इस शिकायत को लेकर व्यापक चिंता है।

- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए श्री अजीत के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- रजिस्ट्रार इस मामले की उचित और निष्पक्ष जाँच कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
- यौन उत्पीड़न को रोकने और छात्रों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु उन्हें कौन से दीर्घकालिक संस्थागत सुधार प्रस्तावित करने चाहिए?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Mr. Ajit is the Registrar of a prestigious public university renowned for its contributions to social sciences and international research collaborations. The university receives significant funding from global institutions, including a prominent US-based foundation, which supports its Center for Policy Studies. Recently, the university has been rocked by a serious allegation of sexual harassment. A 22-year-old female postgraduate student has filed a formal complaint with the university's Internal Complaints Committee (ICC). She accuses Dr. Vinayak, a distinguished professor and the Director of the Center for Policy Studies, of sexual harassment. Dr. Vinayak, a well-known academic with numerous publications, is politically connected to a senior leader of the ruling party. He has secured over ₹50 crore in international grants for the university over the past five years, making him a key figure in its financial and academic standing.

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

The student's complaint details multiple incidents over six months which includes inappropriate comments during private mentoring sessions, unsolicited late-night messages and an incident where the professor allegedly touched her inappropriately during a closed-door meeting in his office. She claims these actions created a hostile environment, forcing her to avoid classes and affecting her academic performance. She has provided screenshots of messages and a witness, a fellow student, who overheard some remarks. However, the complaint has triggered conflicting narratives. Two colleagues of Dr. Vinayak, who are also senior faculty, claims the student has a history of "exaggerating" issues and suggests her allegations may be motivated by poor grades in his course. Dr. Vinayak denies the allegations, stating that his interactions were professional and that the messages were taken out of context. He has influential supporters including a Member of Parliament who has publicly praised his contributions. The MP also privately contacted Mr. Ajit, hinting that pursuing the case could jeopardize the university's funding and reputation.

The ICC chaired by a senior female professor, is under pressure to expedite the inquiry within the 90-day timeline mandated by the POSH Act. The US-based foundation has expressed concern, stating that continued funding depends on the university maintaining its reputation for ethical governance. Additionally, an internal email leak suggested an offer by a senior faculty to the student for "settling" the matter and a scholarship in return to withdraw her complaint. It has further escalated tensions. As Registrar, Mr. Ajit is responsible for ensuring that the ICC process is fair, transparent and compliant with the POSH Act, while managing the university's reputation, funding and internal academic structure. The Vice-Chancellor, under pressure from the governing council, has asked the registrar to recommend a course of action that balances justice for the student with the university's interests. There is a widespread concern over the complaint amidst rise in heinous sexual crimes against female students in educational institutions across the country.

- Identify the ethical issues involved in the case. What are the options available to Mr. Ajit to tackle the above situation?
- How can the registrar ensure a fair and impartial investigation into the matter?
- What long-term institutional reforms should he propose to prevent sexual harassment and ensure a safe, inclusive environment for students?

20

Q 9. आप एक तेजी से शहरीकृत हो रहे जिले के जिला कलेक्टर हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य में शहरी केंद्रों के साथ-साथ वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। जिले को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरी बाजारों में चोरी और चैन-स्नैचिंग के बढ़ते छोटे-मोटे अपराध, नदी किनारे अवैध रेत खनन, निचले इलाकों में बार-बार आने वाली बाढ़ और सीमा पार से होने वाली तस्करी की गतिविधियाँ। हाल ही में ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल ड्रग्स और छोटे हथियारों जैसे प्रतिबंधित सामान गिराने के लिए किया गया था। इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और सीमा सतर्कता के लिए ड्रोन तैनात करने हेतु एक पायलट परियोजना, "सुरक्षित जिला ड्रोन कार्यक्रम" को मंजूरी दी है। ये ड्रोन उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरों, चेहरे की पहचान और थर्मल इमेजिंग क्षमताओं से लैस होंगे, जो पुलिस और आपदा प्रबंधन इकाइयों को रीयल-टाइम डेटा ट्रांसमिशन में सक्षम होंगे। यह परियोजना ड्रोन नियम 2021 के तहत संचालित हो रही है, जिसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण और उड़ान अनुमति की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें डेटा गोपनीयता पर स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव है।

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

इस पहल ने शुरू से ही विवाद खड़ा कर दिया है। शहरी निवासियों की शिकायत है कि बाजारों में ड्रोन मँडरा रहे हैं और बिना अनुमति के खरीदारों की तस्वीरें ले रहे हैं, जिससे निजता के हनन का खतरा बढ़ रहा है। पिछले महीने, एक ड्रोन ने किसी गाँव में एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की और एक ठेकेदार द्वारा गलती से वह फुटेज ऑनलाइन लीक कर दी गई जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। नदी किनारे के इलाकों के किसान, जहाँ ड्रोन अवैध रेत खनन की निगरानी करते हैं, इस बात से नाराज हैं कि ड्रोन संचालन का प्रबंधन करने वाली कंपनी ने बिना अनुमति के उनकी फसल का डेटा एक कृषि कंपनी के साथ साझा कर दिया।

हालांकि, पुलिस ने ड्रोन की तैनाती के बाद से बाजारों में छोटे-मोटे अपराधों में 30% की गिरावट दर्ज की है और आपदा प्रबंधन दल हाल ही में आई बाढ़ के दौरान फँसे हुए ग्रामीणों का पता लगाकर 20 लोगों की जान बचाने का श्रेय ड्रोन को देते हैं। सीमा सुरक्षा बल पिछले महीने तस्करी के दो प्रयासों का हवाला देते हुए ड्रोन के इस्तेमाल का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं। ड्रोन संचालक निजी कंपनी का दावा है कि उसकी तकनीक सुरक्षित है, लेकिन हाल ही में एक ड्रोन को हैक करके रिहायशी इलाके के ऊपर मोड़ने की घटना ने साइबर सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। ऐसी भी खबरें हैं कि पुलिस कथित तौर पर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल कर रही है। सिविल सोसाइटी समूहों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कड़े नियमों और सार्वजनिक परामर्श की माँग की थी। जिला कलेक्टर के रूप में आपको सुरक्षित जिला ड्रोन कार्यक्रम की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अपराध, आपदाओं और सीमा सुरक्षा से निपटें, साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और सामुदायिक चिंताओं का समाधान करें। आपको ड्रोन संचालन का प्रबंधन करने, हितधारकों को शामिल करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा विकसित करना होगा, और साथ ही मौजूदा नियमों का पालन भी करना होगा।

- नागरिक समूहों द्वारा पायलट परियोजना को रोकने की माँग पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी?
- पायलट परियोजना को लागू करने में आपके निर्णयों का मार्गदर्शन कौन से नैतिक सिद्धांत करेंगे?
- आप जन सुरक्षा के लिए ड्रोन के लाभों को सुनिश्चित करते हुए, उनके दुरुपयोग, जैसे अनधिकृत निगरानी या कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना, को रोकने हेतु क्या कदम उठाएँगे?
- आप नागरिकों को ड्रोन कार्यक्रम के लाभों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने और भय और भ्रांतियों को कम करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान कैसे तैयार करेंगे?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

You are the District Collector of a rapidly urbanising district known for its mix of urban centers as well as forested hilly areas in a state sharing international border. The district faces multiple pressing challenges such as rising petty crimes of theft and chain-snatching in crowded urban markets, illegal sand mining along riverbanks, frequent flash floods in low-lying villages, and occasional smuggling activities across the border. There were recent incidents where drones were used to drop contraband like drugs and small arms. To tackle these issues,

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

the state government has approved a pilot project, “Safe District Drone Program,” to deploy drones for surveillance, disaster response and border monitoring. The drones would be equipped with high-resolution cameras, facial recognition and thermal imaging, capable of real-time data transmission to police and disaster management units. The project operates under the Drone Rules 2021, requiring registration and flight permissions via the Digital Sky platform, but lacks clear guidelines on data privacy.

The initiative has stirred controversy since the very beginning. Urban residents complain about drones hovering over markets capturing footage of shoppers without their consent, raising fears of privacy invasion. Last month, a drone recorded a private family event in a village, and the footage was accidentally leaked online by a contractor, sparking outrage. Farmers near the riverbanks, where drones monitor illegal sand mining, are upset because the company managing drone operations shared their crop data with an agribusiness without permission.

The police, however, have reported a 30% drop in petty crimes in markets since drone deployment and disaster management teams credit drones with saving 20 lives during a recent flood by locating stranded villagers. Border security forces insist on expanding drone use, citing two intercepted smuggling attempts last month. The private company claims its technology is secure but a recent incident where a drone was hacked and diverted over a residential area exposed cybersecurity gaps. There are also reports of police allegedly using drone footage to target activists. Civil society groups had demanded stricter regulations and public consultation before rolling out the pilot project. As District Collector, you are tasked with overseeing the Safe District Drone Program, ensuring it addresses crime, disasters and border security while protecting citizens’ rights and addressing community concerns. You must develop a practical framework to manage drone operations, engage stakeholders, and prevent misuse, all while complying with existing regulations.

- What would be your immediate response to the demand of halting the pilot project from citizens’ groups?
- What ethical principles would guide your decisions in implementing the pilot project?
- What steps would you take to prevent misuse of drones, like unauthorized surveillance or targeting of activists, while ensuring their benefits for public safety?
- How would you design a public awareness campaign to educate citizens about the drone program’s benefits and safeguards, reducing fears and misconceptions?

20

(Answer in 250 words)

- Q10.** 38 वर्षीय रत्ना एक तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप में वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो स्किनकेयर मेकअप उत्पादों में विशेषज्ञता रखती हैं। 2020 में स्थापित इस कंपनी ने अपनी पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडिंग के लिए लोकप्रियता हासिल की है, जो “स्वच्छ, क्रूरता-मुक्त और टिकाऊ” सौंदर्य प्रसाधनों के वादे के साथ मिलेनियल्स को लक्षित करती है। कंपनी का नवीनतम प्रमुख उत्पाद, “ग्लोप्योर” नामक एक प्रीमियम फेस स्क्रब, एक बड़ी सफलता रही है, जिसने अकेले 2024 में कंपनी के राजस्व में ₹ 10 करोड़ का योगदान दिया और इसकी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से 200 स्थानीय नौकरियां सृजित हुईं। हालांकि, उत्पाद विकास और अनुपालन की देखरेख करने वाली वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में रत्ना ने एक परेशान करने वाली समस्या का सामना कर रही है। ग्लोप्योर में नियामक सीमा से थोड़ा अधिक सांद्रता में माइक्रोप्लास्टिक्स (पॉलीइथाइलीन माइक्रोबीड्स) मौजूद हैं। यह मुद्दा एक आंतरिक ऑडिट के दौरान सामने आया और सुरक्षा टीम के विश्लेषण से अपवर्णन (एक्सफोलिएशन) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीइथाइलीन माइक्रोबीड्स की ग्लोप्योर में मौजूदगी की पुष्टि हुई।

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

ये माइक्रोप्लास्टिक, धूल जाने पर अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों से होकर गुजरते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े हैं, जिनमें अंतःस्त्रावी तंत्र में व्यवधान और हृदय संबंधी समस्याएं शामिल हैं, क्योंकि ये जहरीले रसायनों को अवशोषित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं, जिससे समुद्री जीवन और समुद्री भोजन खाने वाले मनुष्यों पर असर पड़ता है।

रत्ना एक जटिल नैतिक स्थिति का सामना कर रही है। कंपनी के सीईओ को इस उल्लंघन की जानकारी नहीं है क्योंकि त्योहारों के मौसम में बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद को तेजी से तैयार किया गया था। नियामकों को इस मुद्दे की सूचना देने से उत्पाद को बाजार से वापस बुलाया जा सकता है, जिससे कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है, कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इससे एक प्रतिष्ठित उद्यम पूंजी फर्म, जो वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुपालन पर जोर देती है, द्वारा निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। हालाँकि, उल्लंघन को छिपाने से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का जोखिम है, साथ ही गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उजागर किए जाने पर कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक प्रतिक्रिया का भी खतरा है। उत्पादन टीम का तर्क है कि सीमांत अतिरिक्तता नगण्य है और व्यवधान से बचने के लिए उत्पाद को छह महीनों में धीरे-धीरे पुनः तैयार करने का सुझाव देती है। कंपनी में रत्ना के वरिष्ठ, जो लाभप्रदता पर केंद्रित हैं, ब्रांड के बाजार हिस्से की रक्षा के लिए एक विवेकपूर्ण समाधान का आग्रह करते हैं, जबकि विपणन टीम चेतावनी देती है कि सार्वजनिक रूप से उत्पाद वापस बुलाने से ग्राहक छिटक सकते हैं।

- (a) एक घनिष्ठ मित्र के रूप में रत्ना ने आपसे सुझाव के लिए संपर्क किया। आप उन्हें क्या सुझाव देंगे?
- (b) अपने सुझावों को उचित सिद्ध करने के लिए कारण बताएँ।
- (c) इस मामले में कॉर्पोरेट मूल्य उपभोक्ता मूल्यों के साथ कैसे टकराते हैं?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Ratna is a 38-year-old senior manager in a rapidly growing start-up specialising in skincare makeup products. The company, founded in 2020, has gained popularity for its eco-conscious branding, targeting millennials with a promise of “clean, cruelty-free, and sustainable” cosmetics. The company's latest flagship product, a premium face scrub called “GlowPure,” has been a massive success, contributing ₹10 crore to the company's revenue in 2024 alone and creating 200 local jobs through its supply chain. However, as senior manager overseeing product development and compliance, Ratna is facing a troubling issue. GlowPure contains microplastics (polyethylene microbeads) at a concentration marginally exceeding the regulatory threshold. This violation, though small, could lead to penalties and damage the company's reputation as an environmentally responsible brand. The issue surfaced during an internal audit and safety team's analysis confirmed the presence of polyethylene microbeads in GlowPure, used for exfoliation. These microplastics, when washed off pass through wastewater treatment systems and pollute aquatic ecosystems. Microplastics are linked to health risks, including endocrine disruption and cardiovascular issues, as they absorb toxic chemicals and accumulate in the food chain, affecting marine life and humans consuming seafood.

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

Ratna faces a complex ethical situation. The company's CEO is unaware of the violation as the product was fast-tracked to meet market demand during the festive season. Reporting the issue to the regulators could lead to a recall of the product causing immense financial losses to the company, layoffs of employees and reputational damage. It could also jeopardise investment from a reputed venture capital firm, which insists on compliance with global sustainability standards. However, concealing the violation risks harm to consumers' health and the environment as well as legal action and public backlash if exposed by NGOs. The production team argues that marginal excess is negligible and suggests reformulating the product gradually over six months to avoid disruption. Ratna's seniors in the company, focused on profitability, urge a discreet resolution to protect the brand's market share, while the marketing team warns that a public recall could alienate customers.

- (a) As a close friend, Ratna contacted you for suggestions. What course of action would you suggest to her?
- (b) Provide reasons to justify your suggestions.
- (c) In this case, how does corporate values conflict with consumer values?

20

(Answer in 250 words)

Q11. दिनेश भारत के एक प्रमुख सॉफ्टवेयर हब में स्थित एक कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधक हैं। वे सामान्य रूप से युवा कार्यबल और विशेष रूप से अपनी कंपनी के कर्मचारियों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं। पिछले वर्ष उनकी कंपनी के तीन कर्मचारियों, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम थी, को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। चिकित्सा रिपोर्ट और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कई कारकों की ओर इशारा करती है, जिनमें परियोजनाओं की कठिन समय सीमा के कारण अत्यधिक कार्य दबाव, गतिहीन जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतें और अपर्याप्त कार्य-जीवन संतुलन शामिल हैं। कंपनी की तीव्र प्रतिस्पर्धा की संस्कृति, जो प्रदर्शन-आधारित बोनस और “हड़बड़ी” की भावना से प्रेरित है, के कारण कर्मचारियों को अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। यह हाल ही में उस राष्ट्रीय बहस से संबंधित है, जो उत्पादकता बढ़ाने और 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानक कार्य सप्ताह को 70 घंटे बढ़ाने के प्रस्तावों से शुरू हुई है। दिनेश की कंपनी में यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, निखत, देर रात कोडिंग सत्र के दौरान बेहोश हो गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके सहकर्मियों ने बताया कि वह नियमित रूप से भोजन छोड़ती थीं, ऊर्जा पेय पर निर्भर रहती थीं और परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारी दबाव का सामना करती थीं। दिनेश द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग दो-तिहाई कर्मचारी किसी न किसी प्रकार के तनाव की शिकायत करते हैं और उनमें से आधे नियमित व्यायाम नहीं करते हैं और एक-तिहाई की नींद अनियमित है। इस बीच, कई सीईओ वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लंबे समय तक काम करने पर जोर दे रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम (जैसे- मुफ्त योग कक्षाएं, मानसिक स्वास्थ्य वेबिनार) पर्याप्त हैं। हालांकि, समय की कमी के कारण इन कार्यक्रमों का कम उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रमुख उद्योग संघ काम के घंटों को बढ़ाने की पैरवी कर रहा है, यह दावा करते हुए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ेगी, जबकि श्रमिक और ट्रेड यूनियन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों और कम जीवन प्रत्याशा की चेतावनी दे रहे हैं।

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया है, कुछ ने गुमनाम रूप से कंपनी की “विषाक्त कार्य संस्कृति” की आलोचना की है, जिससे मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ है और कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। दिनेश पर कंपनी के विकास लक्ष्यों के अनुरूप काम करने का दबाव है लेकिन कर्मचारी बेहतर कार्य-जीवन संतुलन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के एक समूह ने धमकी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाएंगे।

- दिनेश के सामने आने वाली विभिन्न नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए।
- इस स्थिति में उसके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कीजिए।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वस्थ और टिकाऊ कार्य वातावरण बनाने के लिए दिनेश को कौन से दीर्घकालिक नीतिगत उपाय प्रस्तावित करने चाहिए?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Dinesh is a HR Manager in a company based in one of the major software hubs in India. He is increasingly concerned about a disturbing trend in the young workforce in general and his company's employees in particular. Three employees of his company, all under 30, suffered heart attacks in the past year, with one fatality. Medical reports and employee feedback point to multiple factors including high work pressure due to tight project deadlines, sedentary lifestyles, poor dietary habits, and inadequate work-life balance. The company's culture of intense competition, fueled by performance-based bonuses and a “hustle” ethos, has led to employees working extended hours often late into the night. This aligns with recent national debates, sparked by proposals to increase the standard workweek 70 hours to boost productivity and support India's ambition to become a \$5 trillion economy by 2027. The issue came to a head when a 26-year-old software engineer, Nikhat collapsed during a late-night coding session and was hospitalized for a heart attack. Her colleagues revealed she regularly skipped meals, relied on energy drinks, and faced immense pressure to meet project milestones. An internal survey by Dinesh conducted showed about two-thirds of employees report some form of stress and half of them lack regular exercise and one-third have irregular sleep patterns. Meanwhile, many CEOs are pushing for longer hours to compete with global tech giants, arguing that employee wellness programs (e.g., free yoga classes, mental health webinars) are sufficient. However, these programs are underutilised due to time constraints. Additionally, a prominent industry association is lobbying for extended work hours, claiming it will enhance national productivity, while workers' and trade unions and health experts warn of long-term health risks and reduced life expectancy.

Employees have started voicing concerns on social media, with some anonymously criticizing the company's “toxic work culture,” drawing media attention and risking the company's reputation. Dinesh faces pressure to align with the company's growth goals but employees are demanding better work-life balance, and one group has threatened to escalate the issue at various forums if conditions don't improve.

- Discuss various ethical dilemmas faced by Dinesh.
- Examine various options available to him in this situation.
- What long-term policy measures Dinesh should propose to create a healthy and sustainable work environment aligning with global best practices?

20

(Answer in 250 words)

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

Q12. कीर्ति एक युवा नगर नियोजक हैं जिन्हें हाल ही में भारत के एक महानगर में शहरी विकास विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। शहर में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग है जो इसे सिंगापुर जैसे वैश्विक शहरों को टक्कर देने के लिए झुगियों और अनधिकृत कॉलोनियों से मुक्त एक “विश्व स्तरीय” शहरी केंद्र में बदलने के लिए उत्सुक है। गेटेड सोसायटियों के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, निगम ने 20 साल पुरानी एक झुग्गी बस्ती को गिराने का आदेश दिया है जहाँ हजारों परिवार रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर निर्माण और घरेलू सेवाओं में कार्यरत प्रवासी मजदूर हैं। एक नए व्यावसायिक जिले के पास प्रमुख भूमि पर स्थित इस झुग्गी बस्ती पर शहर के कुलीन और मध्यम वर्ग के निवासी आँख गड़ाए हुए हैं, जिन्होंने संपत्ति के मूल्य और नगर-सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इसे हटाने की याचिका दायर की है।

पिछले सप्ताह बिना किसी पूर्व सूचना या प्रोटोकॉल का पालन किए, बुलडोजरों ने झुग्गी बस्ती में सैकड़ों घरों को गिरा दिया, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित निवासियों को विस्थापित होना पड़ा। यह तोड़फोड़ नगर आयुक्त के आदेश पर की गई, जिन्होंने “जनहित” और आगामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन से पहले परियोजना में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के दबाव का हवाला दिया। निवासियों को घर खाली करने के लिए केवल कुछ घंटे दिए गए, जिससे कई लोग बिना आश्रय, निजी सामान या बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच से वंचित रह गए। स्थ. नीय मीडिया ने सड़कों पर सो रहे परिवारों के भयावह दृश्यों की रिपोर्ट दिखाई और एक वायरल वीडियो में एक गर्भवती महिला को अधिकारियों से गुहार लगाते हुए दिखाया गया, जब उसका घर तोड़ा जा रहा था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। गैर-सरकारी संगठनों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है। कीर्ति से तोड़फोड़ से पहले सलाह नहीं ली गई थी, लेकिन अब उन्हें अगले चरण की देखरेख का काम सौंपा गया है, जिसमें उस झुग्गी बस्ती में बचे हुए घरों को खाली कराना शामिल है। उनकी अंतरात्मा व्यथित है क्योंकि उन्होंने समावेशी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सिविल सेवा में प्रवेश किया था, लेकिन तोड़फोड़ में सहानुभूति की कमी और कानूनी प्रोटोकॉल की अवहेलना उनके मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने इलाके का दौरा किया और निवासियों में से एक अकेली माँ से भेंट की जिसने तोड़फोड़ में अपना सिलाई का व्यवसाय खो दिया, एक दिहाड़ी मजदूर से मिलीं जिसे डर है कि उसके बच्चे घर के बिना स्कूल जाना छोड़ देंगे।

एक शक्तिशाली रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा समर्थित, निकटवर्ती समृद्ध इलाके का रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) कीर्ति पर तोड़फोड़ को शीघ्र पूरा करने का दबाव बना रहा है, यह तर्क देते हुए कि इससे शहर की वैश्विक छवि में सुधार होगा। इस बीच, नगर आयुक्त ने संकेत दिया है कि अनुपालन उनके करियर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित झुग्गीवासियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगाने और पुनर्वास की माँग की गई है। राज्य सरकार, जो एक “झुग्गी-मुक्त” शहर का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है, त्वरित कार्रवाई पर जोर दे रही है, लेकिन पुनर्वास योजनाएँ अस्पष्ट हैं, केवल 500 अस्थायी आश्रय उपलब्ध हैं, जो आवश्यकता से बहुत कम है।

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

- (a) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
- (b) कीर्ति को अपनी अंतरात्मा में नैतिक संघर्ष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए?
- (c) समाज के कमजोर वर्गों के लिए समावेशी स्थानों के बिना एक विश्व स्तरीय शहर की नैतिक समस्याएँ क्या हैं?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Kirti is a young town planner recently appointed as the Assistant Commissioner of the Urban Development Department in a metropolitan city in India. The city has a burgeoning middle class eager to transform it into a “world-class” urban center, free of slums and unauthorized colonies, to rival global cities like Singapore. Receiving feedback from various Resident Welfare Associations (RWAs) of gated societies, the corporation has ordered the demolition of a 20-year-old slum housing thousands of families, mostly migrant workers employed in construction and domestic services. The slum located on prime land near a new business district is seen as an eyesore by the city’s elite and middle-class residents, who have petitioned for its removal to enhance property values and aesthetics.

Last week, without prior notice or adherence to protocols, bulldozers demolished hundreds of homes in the slum settlement, displacing residents, including women, children and elderly individuals. The demolition was executed on the orders of the Municipal Commissioner, who cited “public interest” and pressure from the state government to expedite the project before an upcoming international trade summit. Residents were given only hours to evacuate, leaving many without shelter, personal belongings, or access to basic amenities. Local media reported harrowing scenes of families sleeping on streets and a viral video showed a pregnant woman pleading with officials as her home was razed, sparking public outrage. NGOs have condemned the action, alleging violations of human rights. Kirti was not consulted before the demolition but is now tasked with overseeing the next phase, which involves clearing the remaining homes in that slum. Her conscience is troubled as she joined the civil service inspired by a vision of inclusive development but the demolition’s lack of empathy and disregard for legal protocols conflicts with her values. She visited the locality and met residents like a single mother who lost her tailoring business in the demolition, a daily-wage labourer who fears his children will drop out of school without a home.

The Residents’ Welfare Association (RWA) of an adjacent affluent neighborhood, backed by a powerful real estate developer, is pressuring Kirti to complete the demolition swiftly, arguing it will boost the city’s global image. Meanwhile, the Municipal Commissioner has hinted that compliance is crucial for her career progression. However, a group of slum dwellers, supported by NGOs, has filed a petition in the High Court, seeking a stay on further demolitions and demanding rehabilitation. The state government, keen on showcasing a “slum-free” city, is pushing for rapid action, but rehabilitation plans are vague, with only 500 temporary shelters available, far short of what’s needed.

- (a) What are the ethical issues involved in this case?
- (b) What course of action should Kirti choose to address the ethical conflict in her conscience?
- (c) What are the ethical problems with a world class city with no inclusive spaces for weaker sections of society?

20

(Answer in 250 words)

- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048



- ✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
- ✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
- ✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048